

बिहार राज्य

बनाम

पशुपति सिंह एवं अन्य तथा इसके विपरीत

24 सितंबर, 1973

[एच. आर. खन्ना और ए. अलागिरीस्वामी, न्यायमूर्तिगण]

*दंड विधि—व्यवहार और प्रक्रिया—क्या शिनाख्त चार्ट में पूर्ण कथन होना चाहिए।*

दो मृतक, पति और पत्नी, अपनी बेटी और नौकर के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक छोटे स्टेशन पर दो अपीलकर्ता और एक अन्य सह-अभियुक्त, जो अभी भी फरार है, घातक हथियारों से लैस होकर डिब्बे में घुस गए। पति और पत्नी को लूटा गया और उसके बाद हुई हाथापाई में दोनों को घातक चोटें आईं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद मृतक की बेटी और नौकर द्वारा उनकी पहचान की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

उच्च न्यायालय ने, *अन्य बातों के साथ-साथ* यह धारित करते हुए कि परीक्षण शिनाख्त चार्ट में पहले अभियुक्त द्वारा मृतकों में से एक पर हमले के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था, दोनों अभियुक्तों को भा.दं.वि. की धारा 302 के तहत अपराध से बरी कर दिया।

धारा 394 के संबंध में अपीलकर्ताओं की अपील को खारिज करते हुए और धारा 302 के संबंध में राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए।

अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा परीक्षण शिनाख्त चार्ट का किया गया उपयोग त्रुटिपूर्ण था। परीक्षण शिनाख्त चार्ट से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसमें पूर्ण कथन शामिल हो। दोनों अभियुक्तों की पहचान दो अभियोजन साक्षियों द्वारा की गई थी और उन दोनों ने दूसरे अभियुक्त द्वारा मृतकों में से एक पर हमले की बात कही थी। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता कि पहले अभियुक्त ने किसी को चोट

नहीं पहुंचाई या किसी ने दूसरे मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई। उच्च न्यायालय ने भी यह नहीं पाया कि पहले अभियुक्त ने दोनों मृतकों में से किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। [745 ई]

यदि यह कहना कठिन था कि कौन सी चोट किस अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई थी, तो स्वाभाविक निष्कर्ष यह होगा कि तीनों अभियुक्तों ने प्रत्येक मृतक पर एक-एक चोट पहुंचाई। चूंकि दो अभियुक्तों के हाथों में मौजूद हथियारों से पहुंचाई गई चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं, इसलिए दोनों अभियुक्त हत्या के समान रूप से दोषी थे। यह तथ्य कि उन्होंने हत्या करने के इरादे से शुरुआत नहीं की होगी बल्कि केवल लूटपाट करने के लिए की होगी, प्रासंगिक नहीं था। चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं और इसलिए, अभियुक्त हत्या के दोषी होंगे। [745 जी-एच]

अपराध की तिथि और अपील की समाप्ति के बीच के लंबे अंतराल और अभियुक्तों द्वारा झेली गई मानसिक यंत्रणा को ध्यान में रखते हुए, न्याय का उद्देश्य पूरा होगा यदि आजीवन कारावास की सजा दी जाए। [746 बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1970 की आपराधिक अपील संख्या 53 और 54।

1969 के 15 अक्टूबर के पटना उच्च न्यायालय के 1969 की आपराधिक अपील संख्या 150, 152 और 167 में दिए गए निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता (अपील 53/70 में) और उत्तरदाता (अपील 54/70 में) के लिए *यू. एस. प्रसाद, एस.के. सिन्हा, बी. बी. सिन्हा और डी. पी. मुकर्जी*।

उत्तरदाता (अपील 53/70 में) और अपीलकर्ताओं (अपील 54/70 में) के लिए *यू. पी. सिंह*।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

**अलागिरीस्वामी, न्यायमूर्ति।** 1970 की आपराधिक अपील संख्या 54 के दो अपीलकर्ताओं पर भागलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 394 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोनों

अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें दी गई मृत्युदंड की पुष्टि के लिए किए गए संदर्भ और उनके द्वारा दायर दो अपीलों पर, पटना उच्च न्यायालय ने धारा 394 के तहत उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन उन्हें धारा 302 के तहत अपराध से बरी कर दिया। अभियुक्तों के साथ-साथ बिहार राज्य ने भी इस न्यायालय में अपील की है, अभियुक्तों ने धारा 394 के तहत अपनी दोषसिद्धि के संबंध में और राज्य ने धारा 302 के तहत उनकी दोषमुक्ति के विरुद्ध। इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

भागलपुर निवासी राम प्रसाद मंडल, उनकी पत्नी रुक्मिणी और उनकी बेटी पुष्पा देवी वेल्लोर से लौट रहे थे, जहाँ बेटी का इलाज हुआ था। वे 6-4-1965 को हावड़ा दानापुर फास्ट पैसेंजर से कलकत्ता से भागलपुर की यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनका नौकर मोहन लाल (अ. सा. 1) भी था। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर अपीलकर्ता पशुपति सिंह उनके डिब्बे में घुसा और जब ट्रेन घोघा रेलवे स्टेशन पहुँची, तो अपीलकर्ता सुतली राय और एक अन्य अभियुक्त, जो अब फरार है, उस डिब्बे में घुस गए। दोनों अपीलकर्ताओं के हाथ में गुप्ती थी। कुछ समय बाद फरार अभियुक्त ने एक छुरा निकाला और राम प्रसाद मंडल से उसके पास जो कुछ भी था उसे देने को कहा। अपीलकर्ता पशुपति सिंह मोहन लाल के पास खड़ा हो गया और सुतली राय रुक्मिणी देवी के पास। राम प्रसाद मंडल ने उसके पास जो कुछ भी था उसे देने की पेशकश की लेकिन फरार अभियुक्त का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस पर तीनों अभियुक्तों ने राम प्रसाद मंडल पर हमला कर दिया और वह नीचे गिर गया। रुक्मिणी देवी ने उनसे मारपीट न करने को कहा और अपने एक हाथ से चूड़ियाँ निकालकर एक अभियुक्त को सोंप दीं। तीनों अभियुक्तों में से एक ने उनका हार छीन लिया और जब उन्होंने खतरे की जंजीर खींचने की कोशिश की, तो तीनों ने अपने हाथों में मौजूद हथियारों से उन पर हमला किया और वह भी नीचे गिर गई। मोहन लाल जिसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, उस पर पशुपति सिंह ने गुप्ती से हमला किया और उसकी कलाई घड़ी और उसके पास मौजूद साठ-

सत्तर रुपये छीन लिए। पुष्पा देवी ने अपने गहने सौंप दिए। इसके बाद बदमाशों ने जंजीर खींची और ट्रेन से उतर गए। जब ट्रेन रुकी, तो फायरमैन अब्दुल अजीज (अ. सा. 8) डिब्बे में आया और उसने पुष्पा को रोते हुए और राम प्रसाद मंडल तथा रुक्मिणी देवी को घायल अवस्था में पाया। गार्ड (अ. सा. 10) भी वहाँ आया। अगले रेलवे स्टेशन सबौर पर सहायक स्टेशन मास्टर (अ. सा. 5) ने उन्हें भागलपुर जाने की सलाह दी क्योंकि सबौर में चिकित्सा सहायता मिलने में देरी होगी। उसने भागलपुर रेलवे स्टेशन को भी सूचित किया। ट्रेन 7-4-1965 को लगभग 1:15 बजे भागलपुर पहुँची। अ. सा. 10 ने रेलवे पुलिस के प्रभारी अधिकारी को एक लिखित प्रतिवेदन, प्रदर्श 2, सौंपा, जिसके आधार पर अ. सा. 12 द्वारा लगभग 1:45 बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन तैयार किया गया। इस समय तक राम प्रसाद मंडल की मृत्यु हो चुकी थी और रुक्मिणी देवी की हालत गंभीर थी। उन सभी को अस्पताल भेजा गया जहाँ सुबह 6 बजे रुक्मिणी देवी की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता सुतली राय ने 10 मई, 1965 को आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि पशुपति सिंह को 11 मई, 1965 को गिरफ्तार किया गया। 24 मई, 1965 को आयोजित परीक्षण शिनाख्त परेड में मोहन लाल और पुष्पा देवी ने दोनों की पहचान की। यथासमय दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसका परिणाम पहले ही बताया जा चुका है।

पशुपति सिंह का बचाव यह था कि वह निर्दोष था, कि दो चश्मदीद साक्षियों को घटना से पहले उसे जानने के अवसर मिले थे और शिनाख्त परेड से पहले उसे उन्हें दिखाया गया था। सुतली राय ने भी आरोप लगाया कि उसे शिनाख्त साक्षियों को दिखाया गया था। हम संतुष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष कि उन्होंने हमलावरों की उचित पहचान की थी, साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। अगर पशुपति सिंह और अ. सा. 1 व 2 के आरोपों के अनुसार, उन्होंने हमलावरों की सही पहचान की थी, तो यह सबूतों के सही मूल्यांकन पर आधारित है। अपीलकर्ताओं को जिस अपराध से बरी किया गया था, उस प्रश्न पर हम बाद में विचार करेंगे।

अधीनस्थ न्यायालयों और इस न्यायालय के समक्ष कई सुझाव रखे गए, जिनमें से कुछ एक-दूसरे के विपरीत थे, और उनमें से कोई भी अ. सा. 1 और 2 की सत्यता को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला नहीं था। अधीनस्थ न्यायालयों की तरह हमें भी वे सभी निराधार लगे। यदि जैसा कि पशुपति सिंह द्वारा आरोप लगाया गया है, अ. सा. 1 और 2 उसे पहले से जानते होते, तो शिनाख्त परेड से पहले उन्हें उसे दिखाने की शायद ही कोई आवश्यकता होती। इसके अलावा, अ. सा. 1 और 2, यदि वे पशुपति सिंह को पहले से जानते होते, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया होता कि वे हमलावरों में से एक को जानते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं, भले ही वे उसका नाम न जानते हों। यहाँ ऐसी बात नहीं थी। अ. सा. 1 या अ. सा. 2 के पास अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं है। उनके प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो उनकी विश्वसनीयता को डिगा सके। राम प्रसाद मंडल की उसके भतीजे तारकेश्वर प्रसाद द्वारा हत्या किए जाने की संभावना के बारे में बहुत अस्पष्ट और बेबुनियाद सुझाव दिए गए थे; कि राम प्रसाद मंडल के बेटे की जान लेने की कोशिश की गई थी और वही व्यक्ति राम प्रसाद मंडल की हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकता था; कि राम प्रसाद ने उस कारण से उसे मार दिया होगा। इन सुझावों में से किसी में भी कोई दम नहीं है। यह भी सुझाव दिया गया था कि जब घटना हुई तब मोहन लाल डिब्बे में नहीं था, क्योंकि तारकेश्वर प्रसाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने उसके माध्यम से कलकत्ता पैसे भेजे थे, का परीक्षण नहीं किया गया था और किसी और ने उसके कलकत्ता जाने की बात नहीं कही थी। केवल दो होल्डॉल की उपस्थिति और पुष्पा देवी का मोहन लाल के होल्डॉल पर बैठने की असंभवता के आधार पर भी कुछ तर्क देने की कोशिश की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि घटना के समय मोहन लाल डिब्बे में मौजूद था। पुष्पा देवी से उनके प्रति-परीक्षण में यह भी नहीं पूछा गया था कि मोहन लाल मौजूद नहीं था। न ही मोहन लाल के सामने ऐसा कोई सुझाव रखा गया था। हमारा मानना है कि साक्ष्य स्पष्ट

रूप से स्थापित करते हैं कि ट्रेन में हुई लूटपाट और हत्याओं के लिए दो अपीलकर्ता और फरार अभियुक्त ही जिम्मेदार थे।

हम इस मामले के सभी साक्ष्यों या उन सभी बिंदुओं का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते जो तर्कों के दौरान उठाए गए थे क्योंकि हम नहीं मानते कि वे लूटपाट और हत्याओं के केंद्रीय बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों को किसी भी तरह से कमजोर करते हैं और यह न्यायालय सामान्यतः साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन नहीं करता है सिवाय न्याय की गंभीर विफलता के मामलों में।

अब हम हत्या के आरोप से दो अपीलकर्ताओं को बरी किए जाने के विरुद्ध बिहार राज्य द्वारा दायर अपील पर आते हैं। हमारी राय है कि इस बिंदु पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीशों ने दोनों मृतकों पर पाई गई चोटों और चिकित्सा साक्ष्य का उल्लेख किया कि दोनों मृतकों में से प्रत्येक पर पाई गई 3 चोटों में से एक खंजर से कारित की जा सकती थी जबकि अन्य दो खंजर से कारित की जा सकती थीं। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार, खंजर की चोटें फरार अभियुक्त द्वारा दी गई थीं जबकि अन्य दो चोटें दो अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई थीं। विद्वान न्यायाधीशों ने सोचा कि पशुपति सिंह जो मोहन लाल पर पहरा दे रहा था, वह उसे छोड़कर राम प्रसाद मंडल और रुक्मिणी देवी पर हमला करने नहीं गया होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि परीक्षण शिनाख्त चार्ट में रुक्मिणी देवी पर सुतली राय द्वारा विशिष्ट हमले का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने माना कि जब हथियार पेश नहीं किए गए और हथियारों का कोई विवरण नहीं दिया गया, तो यह धारित करना कठिन था कि एक विशेष चोट फरार अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई थी जबकि अन्य चोटें दो अपीलकर्ताओं द्वारा पहुंचाई गई थीं। उनकी राय थी कि यह निष्कर्ष नहीं लगाया जा सकता कि बदमाश लूटपाट करते समय हत्या करना चाहते थे, और हत्या करने का कोई इरादा या सामान्य इरादा नहीं था। यही कारण था जिसने उन्हें यह धारित करने के लिए प्रेरित किया कि अपीलकर्ता हत्या के अपराध के दोषी नहीं थे। हमारी राय है कि उच्च

न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा परीक्षण शिनाख्त चार्ट का किया गया उपयोग त्रुटिपूर्ण है। परीक्षण शिनाख्त चार्ट से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही की जा सकती है कि इसमें पूर्ण कथन हो। यह दर्शाता है कि अ. सा. 1 ने दोनों अभियुक्तों की पहचान की और उसकी कलाई घड़ी तथा पैसे लूट लिए गए। इसमें यह भी उल्लेख है कि उसने यह भी कहा कि सुतली राय ने राम प्रसाद मंडल पर *गुसी* से हमला किया। अ. सा. 2, पुष्पा देवी, के बारे में कहा जाता है कि उसने दोनों अपीलकर्ताओं की पहचान की और कहा कि उसने पशुपति सिंह को मोहन लाल पर हमला करते और उसकी घड़ी लूटते देखा और सुतली राय ने राम प्रसाद मंडल पर *गुसी* से हमला किया। यह देखा जाएगा कि यहाँ उल्लेख केवल सुतली राय द्वारा राम प्रसाद मंडल पर *गुसी* से हमला करने के बारे में है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता, और न ही विद्वान न्यायाधीशों का कहना है कि पशुपति सिंह ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और किसी ने रुक्मिणी देवी को चोट नहीं पहुंचाई। हम इसे तब समझते यदि विद्वान न्यायाधीशों ने यह कहा होता कि पशुपति सिंह ने मृतकों में से किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई। वे ऐसा नहीं कहते। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि यदि यह कहना कठिन था कि कौन सी चोट किस अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई थी, तो स्वाभाविक निष्कर्ष यह होगा कि तीनों अभियुक्तों ने प्रत्येक मृतक पर एक-एक चोट पहुंचाई। चूंकि *गुसी* द्वारा पहुंचाई गई चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं, इसलिए दोनों अपीलकर्ता हत्या के समान रूप से दोषी हैं। यह तथ्य कि वे हत्या करने के इरादे से नहीं बल्कि केवल लूटपाट करने के इरादे से निकले होंगे, प्रासंगिक नहीं है। यदि उन्होंने ऐसी चोटें पहुंचाई हैं जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वे हत्या के दोषी होंगे। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से भिन्न मत रखते हुए यह धारित करते हैं कि दोनों अभियुक्त हत्या के अपराध के दोषी हैं। हालांकि, इस तथ्य को देखते हुए कि अपराध की तिथि और अब के बीच एक लंबा अंतराल हो गया है और अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने तक मृत्युदंड की सजा के तहत रखा

गया था जिससे वे मानसिक यंत्रणा की अवधि से गुजरे होंगे, हम मानते हैं कि न्याय का उद्देश्य इस मामले की परिस्थितियों में पूरा होगा यदि दोनों अपीलकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। राज्य की अपील को इस हद तक स्वीकार किया जाता है और अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज किया जाता है।

पी.बी.आर.

1970 की आपराधिक अपील 53 स्वीकार की गई..

1970 की आपराधिक अपील 54 खारिज की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।